



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917  
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH, 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

उद्योग मंत्रालय

(ओद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

कानून 281(अ)/18कक्ष/आई०डी०आर०ए०/95.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या-320(अ)/18कक्ष/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मौसम अपार्क जिप्पर कपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण ओद्योगिक उपकरण का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक्ष की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष को अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और संचित,

बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपकरण का प्रबंध प्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त भ्रादेश तीन बर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1995 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे। (देखिये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश) :

सं० का०आ० 246(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/82, तारीख 25 मई, 1982  
 सं० का०आ० 832(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/82, तारीख 24 नवम्बर, 1982  
 सं० का०आ० 385(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/83, तारीख 31 मार्च, 1983  
 सं० का०आ० 872(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/83, तारीख 30 नवम्बर, 1983  
 सं० का०आ० 472(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/84, तारीख 28 जून, 1984  
 सं० का०आ० 975(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984  
 सं० का०आ० 275(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/85, तारीख 29 मार्च, 1985  
 सं० का०आ० 146(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/86, तारीख 31 मार्च, 1986  
 सं०का०आ० 266(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/87, तारीख 30 मार्च, 1987  
 सं० का०आ० 326(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/88, तारीख 30 मार्च, 1988  
 सं० का०आ० 247(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/89, तारीख 31 मार्च, 1989  
 सं० का०आ० 277(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/90, तारीख 30 मार्च, 1990  
 सं० का०आ० 214(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/91, तारीख 26 मार्च, 1991  
 सं० का०आ० 250(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/92, तारीख 30 मार्च, 1992  
 सं० का०आ० 219(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/93, तारीख 31 मार्च, 1993  
 सं० का०आ० 278(भ) / 18कक/प्राई०डी०आर०ए०/94, तारीख 31 मार्च, 1994

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त भ्रादेश 31 मार्च, 1996 तक की जिसमें यह तारीख भी शामिल है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुके साथ परिवर्तित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश, 31 मार्च, 1996 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी जना रहेगा।

[फॉर्म० 2/3/80—संयोगस०/आई०प्रार०एग०]  
प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)  
ORDER  
New Delhi, the 31st March, 1995

S.O. 281(L)|18AA|IDRA|95.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1995 (Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982,  
 S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,  
 S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,  
 S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,  
 S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,  
 S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,  
 S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985  
 S.O. 146(E)|18AA|IDRA|85, dated the 31st March, 1985.

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,  
S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,  
S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,  
S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,  
S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,  
S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92, dated the 30th March, 1992,  
S.O. 219(E)|18AA|IDRA|93, dated the 31st March, 1993 and  
S.O. 278(E)|18AA|IDRA|94, dated the 31st March, 1994.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1996.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1996.

[F. No. 2(23)|80-CUS|IRS]  
PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.